भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-05
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

सीमा पर स्थित स्कूल

†5. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर शून्य-लाइन/कंटीले तार क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों और परिवारों, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटता के कारण निरंतर खतरे और अनिश्चितता में रहते हैं और बाढ़ के दौरान बुरी तरह प्रभावित होते हैं, के लिए किसी विशेष शैक्षिक योजना या नीति पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इन सुभेद्य क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षण सुविधाओं और योग्य कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से सुसज्जित सीमा पर स्थित स्कूलों की स्थापना के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं;
(ग) सुरक्षा व्यवधानों के दौरान निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवासीय स्कूली शिक्षा या परिवहन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) इन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, परामर्श सहायता, उच्च शिक्षा में आरक्षण की पेशकश का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) संभावित युद्ध जैसे वातावरण में दैनिक जोखिम और बाढ़ से प्रभावित इन हाशिए पर पड़े छात्रों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए तत्काल उपाय की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से **(ङ):** शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पंजाब सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केन्द्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है।

समग्र शिक्षा के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घटक (केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित) के तहत, उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। निर्धारित समय अवधि में विशिष्ट कार्यकलाप संचालित करने के लिए, पंजाब राज्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (वीवीपी-II) के तहत शामिल किया गया है।

पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार अमृतसर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ जीरो-लाइन/कंटीले तार वाले क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों को पहले से ही मध्याह्न भोजन सुविधा, निःशुल्क किताबें, निःशुल्क यूनिफॉर्म, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, खेल सुविधाएं और कई अन्य शैक्षिक गतिविधियां प्रदान कर रही है। हाल ही में आई बाढ़ के दौरान कई गैर सरकारी संगठन छात्रों की मदद के लिए आगे आए और बैग, किताबें और ट्रैक सूट आदि वितरित किए। बाढ़ के बाद, विभाग ने स्कूल नवीनीकरण शुरू किया।

इसके अलावा, जैसा कि पंजाब राज्य द्वारा सूचित किया गया है, अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी स्कूल प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के साथ-साथ योग्य कंप्यूटर संकाय से सुसज्जित हैं। समग्र शिक्षा के तहत, अमृतसर जिले में वित्त वर्ष 2025-26 में 188 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 2 स्मार्ट कक्षाओं को अनुमोदन दिया गया है।

पंजाब राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सुरक्षा व्यवधान के दौरान जो स्कूल बंद रहे, कक्षाओं को पास के सुरक्षित स्कूलों और स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। एक बार जब स्थिति सामान्य हो जाती है, तो नियमित कक्षाएं फिर से शुरू हो जाती हैं, स्कूल के कर्मचारी व्यवस्थित रूप से पूरे लंबित पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद छात्रों की शैक्षणिक प्रगति निर्बाध बनी रहे। इन स्कूलों के अधिकांश छात्र आसपास के क्षेत्रों के निवासी हैं, इसलिए किसी भी आवासीय और परिवहन सुविधा की आवश्यकता नहीं है।

पंजाब राज्य ने यह भी सूचित किया है कि इन स्कूलों के छात्रों के लिए कोई विशेष छात्रवृत्ति योजना नहीं है लेकिन सरकार तीन केन्द्र प्रायोजित और पांच राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है। इन स्कूलों को मार्गदर्शन और परामर्श अनुदान प्रदान किया जाता है। इन स्कूलों में गाइडेंस और काउंसलर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं।

****